

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 90/XVIII(3)/2016-20(01)/2014-श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 4, धारा 5 एवं धारा 6 में क्रमशः सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किये जाने, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई करने तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन करने की व्यवस्था उपबंधित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिले में संबंधित अर्जन निकाय से भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र प्राप्त होने पर सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्-

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी  | अध्यक्ष,    |
| 2. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी   | सदस्य,      |
| 3. तहसीलदार   | सदस्य,      |
| 4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र से एक विषय विशेषज्ञ/इस अध्ययन हेतु नामित गैर सरकारी विशेषज्ञ एजेन्सी | सदस्य,      |
| 5. सम्बन्धित ग्राम के प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य   | सदस्य,      |
| 6. सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल  | सदस्य-सचिव। |

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त समिति द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन लोक प्रयोजन का अवधारण रिपोर्ट सम्यक् प्रकाशन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गव्याल,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014-In section 4, section 5 and section 6 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), provide to preparation of social impact assessment study, to public hearing for social impact assessment and to publication of social impact assessment study respectively, the powers conferred by these sections the Governor is pleased to constitute of following committee for a social impact assessment and to fixation of public purposes on received on indentation letter of the land acquisition from concerning acquire bodies in the district, as follows, namely :-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Concerning SDM                       | Chairman, |
| 2. Concerning Block Development Officer | Member,   |
| 3. Tehsildar                            | Member,   |

( 2 )

4. A subject expert/representative of Non-governmental agencies from the concerning area, nominated by the concerning district magistrate

Member,

5. Pradhan of the concerning village and member of Kshetra Panchyat

Member,

6. Concerning Revenue Deputy Inspector/Lekhpai

Member-Secretary.

2. The Governor is pleased to directed also that the above committee shall provide fixation report for due publication of Social Impact Assessment public purposes to the concerning District Magistrate.

By Order,

D. S. GARBYAL,  
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 27-02-2016, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आ०ई०) 9 राजस्व/141-14-03-2016-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।